कंपनियों की गिरफ्त में डॉक्टर

सुनील

यह एक बुरी खबर है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए तो यह शुभ समाचार है, लेकिन देश के लिए और देश की जनता के लिए बुरा संकेत है। यह देश हित व जन हित पर बहुराष्ट्रीय स्वार्थों की एक और जीत है।

खबर यह है कि देश के चिकित्सकों के सबसे बड़े संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी भारतीय चिकित्सा संघ ने अमरीकी कंपनी पेप्सीको के एक पेय और एक खाद्य पदार्थ को स्वास्थ्य के लिए अच्छा बताते हुए उसका समर्थन करने का फैसला किया है। कुछ ही दिनों में अखबारों में और टी.वी. पर, शहरों में व राजमार्गों पर लगे विज्ञापन पटों पर और कंपनी के पैकेटों पर इस संस्था के पदाधिकारी इनका प्रचार करते हुए दिखाई देंगे।

यह एक कंपनी के ब्रांड विशेष का डॉक्टरों द्वारा प्रचार करने की शुरुआत है। अभी तक यह माना जाता था कि डॉक्टरों या उनके संगठनों को किसी कंपनी के किसी खास उत्पाद का प्रचार करने की मनाही है। चिकित्सक का जो पेशा समाज में सम्मान एवं प्रतिष्ठा का पात्र हुआ करता था, उसके बाज़ारीकरण, व्यावसायीकरण, कंपनीकरण एवं पतन का यह एक नया चरण है।

विडंबना यह है कि अमरीका की पेप्सीको और कोका-कोला नामक इन दो कंपनियों का मुख्य धंधा पूरी दुनिया में शीतल पेय बेचने का है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदेह माने गए हैं। दिल्ली स्थित विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने कुछ सालों पहले यह भी उजागर किया था कि भारत जैसे गरीब देशों में इनकी बोतलों में कीटनाशकों की मात्रा युरोपीय मापदंडों से ज़्यादा रहती है। यानी भारत जैसे गरीब देशों की जनता को ज़्यादा अशुद्ध और ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ें खिलाने में इन कंपनियों को कोई हर्ज़ नहीं दिखाई देता। कंपनियों की कोई नैतिकता नहीं होती, मुनाफा ही उनके लिए सर्वोपरि होता है। ऐसी कंपनियों के पक्ष में प्रचार में उतरने का फैसला करके भारतीय चिकित्सा संघ ने बहुत बड़ी भूल की है।

पेप्सीको कंपनी के दो उत्पादों को इस संघ ने समर्थन देने का फैसला किया है। उनमें से एक ट्रोपिकाना ब्रांड का फलों का रस और दूसरा जई का बना हुआ क्वेकर नामक खाद्य पदार्थ है। ट्रोपिकाना अमरीका में फलों के जूस का एक बहुत पुराना ब्रांड है। इसकी शुरुआत 1947 में हुई थी। अमरीका की दुकानों में सबसे ज़्यादा बिकने वाली वस्तुओं में यह तीसरे नंबर पर है। मुख्य रूप से संतरे, अनन्नास और सेब का रस इस नाम से बेचा जाता था। अपना काराबोरी साम्राज्य फैलाने की प्रक्रिया में अगस्त 1998 में पेप्सीको ने इसे खरीद लिया। कुछ साल पहले इस कंपनी ने भारत में भी फलों का रस पैक करके इस नाम से बेचना शुरू किया। अभी तक पेप्सी कंपनी अपने उत्पादों के प्रचार के लिए बड़े-बड़े फिल्मी सितारों, किक्रेट खिलाड़ियों आदि का सहारा लेती थी। अब उसने भारतीय डॉक्टरों के संगठन को भी पटा लिया है।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि इन दोनों वस्तुओं की जांच करके स्वास्थ्यवर्धक पाए जाने पर ही उन्होंने समर्थन देने का फैसला किया है। किंतु सवाल यह है कि एक खास कंपनी का खास ब्रांड ही क्यों? यदि समर्थन देना ही है तो उन्हें फलों, फलों के रस एवं अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों को देना चाहिए, किसी ब्रांड विशेष को नहीं। बल्कि कंपनियों द्वारा पैक करने की प्रक्रिया में उनको सुरक्षित रखने के लिए और विशिष्ट ज़ायका देने के लिए कुछ रसायन तो मिलाए जाते ही हैं, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होते हैं।

कायदे से भारतीय चिकित्सक संघ को तो यह प्रचार करना चाहिए कि स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे अच्छा है कि लोग ताज़े फल खाएं या स्वयं ताज़ा रस निकालकर पीएं और पाउचों, पैकेटों व डिब्बों के अंदर पैक खाद्य व पेय पदार्थों के चक्कर में ना पड़ें। इनसे देश में प्लास्टिक व

अन्य कचरे की भी बाढ़ आ गई है, जो कुदरत, स्वच्छता और मानव स्वास्थ्य के लिए एक नई समस्या बन गई है।

इंडियन मेडिकल ऐसोसिएशन ने अपनी सफाई में यह भी कहा है कि यह करार गैर-व्यावसायिक है तथा इस समर्थन के बदले में वे कंपनी से कोई धनराशि नहीं ले रहे हैं। लेकिन कंपनी उन्हें वार्षिक सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार जैसे कार्यक्रम आयोजित करने में मदद करेगी। देखा जाए, तो इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। ऐसोसिएशन ने पेप्सी कंपनी के साथ मिलकर दिल्ली एवं मुंबई के 80 स्कूलों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का एक कार्यक्रम भी हाथ में लेने का फैसला किया है। इस विवाद में यह भी पता चला है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसके पहले भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के तीन सामानों को अपना समर्थन दे चुका है। रेकिट बेंकिसर कंपनी का डेटॉल साबुन, प्रोक्टर एंड गेम्बल कंपनी के पेम्पर्स डायपर्स (शिशुओं के पोतड़े) और यूरेका फोर्ब्स कंपनी का पानी शुद्ध करने का उपकरण। एसोसिएशन का दक्षिण दिल्ली में जो दफ्तर है, उसकी महंगी साज-सज्जा और फर्निशिंग का काम यूरेका फोर्ब्स कंपनी ने ही किया है।

देशी-विदेशी मुनाफाखोर कंपनियों के साथ भारतीय चिकित्सा संघ की यह दोस्ती अच्छी बात नहीं है। यह देश के एलोपैथिक चिकित्सकों का संगठन है और पूरे देश में इसके पौने दो लाख सदस्य हैं। सन 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी बेवसाइट में इसके तीन उद्देश्य बताए गए हैं। एक, चिकित्सा विज्ञान को आगे बढ़ाना। दो, भारत में जन स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा में सुधार करना। तीन, चिकित्सा पेशे की गरिमा व सम्मान को बनाए रखना। कंपनियों के उत्पादों की वकालत करके यह संघ इन तीन उद्देश्यों के खिलाफ काम कर रहा है।

वैसे तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का कंपनियों की गिरफ्त में रहना कोई नई बात नहीं है। उसकी हर कॉन्फ्रेंस दवा कंपनियां प्रायोजित करती हैं और भाग लेने वालों को महंगे तोहफे देती हैं। चिकित्सा विज्ञान के शोध व अनुसंधान की लगभग सारी पत्रिकाएं इन कंपनियों के विज्ञापनों से चलती हैं। पश्चिमी देशों में लगभग पूरा अनुसंधान दवा कंपनियों द्वारा करवाया जाता है, जिसमें जन हित से ज़्यादा कंपनी हितों का ख्याल रखा जाता है। इसकी निष्पक्षता, वैज्ञानिकता और उपयोगिता पर कई बार गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। चिकित्सा विज्ञान से जुड़े ज़्यादातर पेटेंट इन कंपनियों के पास ही हैं। ये कंपनियां अपनी नई दवाइयों को लांच करने के लिए कई बार पक्षपात पूर्ण प्रयोग एवं अनुसंधान करवाती हैं। वैश्वीकरण-उदारीकरण-निजीकरण के दौर में भारत सरकार भी इसी रास्ते पर चल पड़ी है। जन हित में शोध व अनुसंधान की अपनी ज़िम्मेदारी से मुंह मोड़कर यह काम पूरी तरह कंपनियों के हवाले करती जा रही हैं। इसे 'सार्वजनिक-निजी सहयोग' (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) का भ्रामक नाम दिया जा रहा है।

हर डॉक्टर के यहां इन दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों की भीड़ लगी रहती है, जो इन्हें उपहार देते रहते हैं। इन दवाइयों को जांचे परखे बगैर अनेक डॉक्टर गैर ज़रूरी दवाइयां लिखते रहते हैं। इनमें उनका कमीशन बंधा होता है। मरीज़ों से कई तरह की गैर ज़रूरी जांचें करवाई जाती हैं, उनमें भी कमीशन होता है। पैसे के लालच में ही कई बार ज़रूरी न होने पर भी ऑपरेशन कर दिए जाते हैं और उनके अन्य विकल्पों को आज़माया नहीं जाता। दवाइयां, जांचें व इलाज बहुत मंहगे होते जा रहे हैं और वहां लूट मची है। यह चिकित्सा क्षेत्र के बढ़ते बाजारीकरण और निजीकरण के दुष्परिणाम हैं।

बेहतर होता कि भारतीय चिकित्सा संघ इन प्रवृतियों को रोकने के लिए कुछ करता। चिकित्सकों की आचार संहिता का बेहतर पालन करवाता और उनमें स्व-अनुशासन को बढ़ावा देता, चिकित्सा के क्षेत्र में मुनाफाखोर कंपनियों की दखलंदाज़ी और उनके प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए कार्यवाही करता और अपने सदस्यों को सचेत व शिक्षित करता, इलाज से वंचित गरीब जनता के लिए कुछ करता। लेकिन इसकी बजाय कंपनियों के साथ गलबहियां करने का फैसला करके उसने गलत दिशा में उठाया है। ***(स्रोत फीचर्स)***